व्यय के संबंध में चौहत्तरवां प्रतिवेदन ।

(2) परिवार कल्याण कार्यक्रम से संबंधित 139वें प्रतिवेदन 8वीं लोक सभा) पर की गई कार्यवाही के संबंध में तेहत्तरवां प्रतिवेदन।

MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

SHRI RAMESHWAR THAKUR : I move the following Motion :—

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the Lok Sabha for the term ending on the 30th April, 1995, and do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct,, seven members from among the members of the House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

SHRI RAMESHWAR THAKUR : I move the following Motion :—

"That this House resolves that the Rajya Sabha do join the Committee of both the Houses on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term ending on the 30th April, 1995, and do proceed to elect, in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, ten members from among the members of the House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR ELECTION TO THE COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

SHRI RAMESHWAR THAKUR : I move the following Motion :—

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public accounts of the Lok Sabha for the term ending on the 30th April, 1995, and do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, seven members from among the members of the House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.

REFERENCES

Rehabilitation of Victims of Maharashtra Earthquake of 30th September, 1993

डा. बापू कालदाते (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से अति विशेष महत्व के प्रश्न की तरफ सदन का और केन्द्रीय मंत्रिमंडल का ध्यान खींचना चाहता हूं । आप जानती हैं कि महाराष्ट्र में 30 सितम्बर को एक बहुत बड़ा भुकम्प आया था। आज सात महीने हो चुके हैं और मैं हाल ही में उस भूकम्पग्रस्त क्षेत्र का दौरा करके आया हूं और वहां के लोगों की दुर्दशा और करुणामय स्थिति को देखकर मुझे खुद को लगा कि कुछ दिन पहले जो सरकार जाग चुकी थी ।

हमने देखा है कि वहां सरकार की तरफ से कोई काम पुनर्वास का नहीं चला है। जो भी थोड़ा-बहुत काम वहां चल रहा है वह सिर्फ वहां की जो जिला परिषद है या पंचायत समिति है, वे लोग कर रहे हैं लेकिन वह भी दवा-दारू का इंतजाम करने और थोड़ा-बहुत लोन देने तक सीमित है। इसको छोड़कर सरकार की तरफ से एक भी गांव के पुनर्निर्माण का काम आज तक शुरू नहीं हुआ है। जो 19 गांव हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां काम शुरू हो चुका है, उनमें से 11 गांव स्वयंसेवी संगठनों की तरफ से बसाए जा रहे हैं यानी 19 में से 11 का काम चालू है और 8 गांवों में अभी तक कोई हलचल नहीं है।

महोदया, मैं खुद वहां होकर आया हूं। आजकल गर्मी के दिन हैं। वहां पर टेम्प्रेरी शेड टीन के बनाए हुए हैं लेकिन इतनी गरमी हो रही है कि लोग अंदर बैठ नहीं सकते। जहां पर यह टेम्प्रेरी शेड्ज बनाए गए हैं, वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं है। तो या तो वे धूप में बैठें या टीन के शेड में बैठें, इसके अलावा उनके सामने कोई चारा नहीं है। जहां पर शेड्ज बनाए गए हैं, वहां पानी का इन्तजाम नहीं है। न रहने की व्यवस्था है, न पानी का इन्तजाम है। मैं जहां जाकर आया हूं वहां स्कैवीज इतने बड़े पैमाने पर फैली है कि आरोग्य सेवाओं के लिए यह प्रमुख काम बन गया है कि इसका निराकरण कैसे करें। यह दर्दनाक सरकार की उपेक्षा का घृणास्पद दर्शन है, मैं ऐसा मानता हूं।

महोदया, जब पहली-पहली बार मुख्यमंत्री वहां गए तो उन्होंने कहा कि पुनर्वास का काम दशहरे को शुरू करेंगे और 26 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। इसमें कोई वास्तविकता नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा कि हम वर्ल्ड बैंक से पैसा ला रहे हैं, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, इसकी बाबत अखबारों में खबरें छप रही हैं लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी गांव के पुनर्वास का काम सरकार की तरफ से अभी तक शुरू नहीं किया गया है। मेरी केन्द्रीय सरकार से शिकायत है कि अब जो वर्ल्ड बैंक से आपको 750 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, तो आपने आज तक उनको क्यों नहीं लोन दिया इस काम के लिए ? जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता तो आप खुद उसको ले लेते। पिछले 6-7 महीनों से कोई काम नहीं हो रहा है। न राज्य सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है, न केन्द्रीय सरकार इसकी तरफ ध्यान दे रही है। मेरी जो जानकारी है, मैं रामजना गांव में गया था, मैंने खुद देखा कि इतनी धूप में इलैक्ट्रिसिटी में गड़बड़ हो जाती है और वहां आग लगने लगी है। इन लोगों के लिए धूप में सड़ने या बाद में बरसात में सड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का जो व्हाईट पेपर है, उससे हमको बहुत चिंता लग रही है। महाराष्ट्र सरकार व्हाईट पेपर में यह कहती है कि यह पुनर्वास का काम 3 सालों तक नहीं होगा। अगर 3 सालों तक नहीं होगा तो क्या आप इतने दिनों तक इसी हालत में लोगों के रखेंगे या इसके लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोई व्यवस्था करेगी जिससे कम खर्च में अच्छा काम चले।

महोदया, वहां की जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, वे भी तीव्र नाराजगी व्यक्त करती हैं कि सरकार का सहयोग नहीं मिलता है। कम पैसे में घर बांधने की एक योजना कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने बनाई है। सरकार कहती है कि 180 रुपए गज का घर होगा लेकिन उन्होंने 70 रुपए में बनाकर दिखा दिया है। मैं देखकर आया हूं कि वहां की मिट्टी, वहां की बालू और थोड़ा सीमेंट मिला दें तो 180 रुपए के बजाय 70 रुपए में उनके लिए मकान बन सकता है। बाबा आमटे के चिरंजीव विकास आमटे वहां पर काम कर रहे हैं। मैं उनके पास गया था। मैंने उन लोगों के द्वारा बनाया हुआ घर देखा और वह मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन सरकार कुछ मदद नहीं करती है बल्कि सोचती है कि ये यहां से चले जाएं। इनको देखेंगे तो लोगों को लगेगा कि इनके घर अच्छे हैं।

तो सरकार की यह नीति अमानुषिक है, तिरस्कारणीय है और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि अब लोग इतने नाराज हो गए हैं कि शायद सरकार के साथ लड़ाई लड़ें। मैं तो लोगों के बीच में जाकर उनसे कह रहा हूं कि अब चुप बैठने से काम नहीं होगा। अब समय आ गया है

कि सरकार के खिलाफ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा और यह जो अमानुषिकता है, उसे दूर करने का प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा । सबसे बड़ी गलती अगर सरकार ने की है तो वह उपक्रमशीलता जो लोगों की है उस को पूर्णतया मार दिया है । सरकार ने जो यह कहा लोगों को कि आप को घर बनाने के लिए सरकार प्रबंध करेगी तो जो खुद घर बनाना चाहते थे उन की उपक्रमशीलता को भी आप ने खत्म कर दिया ।

I see total inertia in that area. People are expecting that the Government would provide them proper shelter. This inertia on the part of the Government is very bad in a democratic country.

लोगों का उपक्रम इसमें चाहिए था । इस योगदान के लिए भी सरकार को कदम उठाना चाहिए और लोगों की जो आज हालत है उस को दुरुस्त करने के लिए प्रयास होना चाहिए, यही मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं ।

धन्यवाद ।

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar) : Madam, I want to associate myself with this sentiment because it is a matter of grave concern not only for Maharashtra but also for the entire country. When the earthquake occurred, all of us felt concerned and, worldwide, there was a wave of sympathy. It was hoped that the decision taken would be fast and speedy, but what my friend points out today is causing us anxiety. I hope the hon. Home Minister who also comes from that State will not be inhibited by the fact that the ruling Chief Minister does not belong in his faction.

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI S. B. CHAVAN) : Madam, I would request the hon. Minister of Agriculture to have a meeting with the Chief Minister of Maharashtra and find out what exactly needs to be done. And the whole thing will have to be expedited in such a manner that some temporary shelters, at least, are provided. ...*(Interruptions)* It might take three years for a permanent construction. But I don't think that until then these people can face the vagaries of nature. That is why it it absolutely necessary that both the things will have to be done simultaneously.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, ...

THE DEPUTY CHAIRMAN :

पहले सतीश प्रधान जी का नाम है । .... (व्यवधान)

Let him also speak and you can support him.

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh) : Can we request Mr. Suresh Kalmadi who represents the Government of Maharashtra to respond ?

THE DEPUTY CHAIRMAN : He is not there in the House. And I do not know whether he represents the Government of Maharashtra or the State of Maharashtra. Yes, Shri Satish Pradhan.

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra) : Madam, thank you very much for giving me an opportunity to speak on the subject. While associating myself with Dr. Bapu Kaldate, I have to bring some more things before the House. Madam, this earthquake occurred at two major places on 30th September, 1993. The present situation is that the construction work which is going on is done by the private parties only. It is they who are doing the construction work. They are working there voluntarily. The Government has constructed shacks barracks etc. there, but no basic amenities have been provided to the people who are residing there. Immediately after the earthquake, they constructed sheds, barracks and things like that. Now, in one shack or a barrack, eight to ten families are residing. There is no privacy also. And now that the summer season has started, it has become very difficult for them to stay at such places. The Maharashtra Government has estimated that the cost of the construction of houses, roads, bridges and the cost incurred for the provision of power supply and other things would come to Rs. 856.10 crores of rupees. From the Chief Minister's Relief Fund, they have collected Rs. 218 crores of

rupees and the Prime Minister has allotted Rs. 104 crores only from the Prime Minister's Relief Fund. This is the most unfortunate thing and is an injustice done to the people of Maharashtra. According to my knowledge, the Prime Minister's Relief Fund has collected a huge amount for the Maharashtra Earthquake Relief. People from all parts of the country have donated thousands of crores of rupees for the Prime Minister's Relief Fund.

Apart from this, according to my knowledge, the international donors donated an amount of 850 million dollars for the Prime Minister's Relief Fund. Though Prime Minister's Relief Fund received such huge amounts, I don't know why only an amount of Rs. 104 crores was passed on to the Maharashtra Government. What happened to the remaining money ? Where has the remaining money gone ? I want to know from the hon. Prime Minister where the money donated for the Maharashtra Earthquake Fund has gone, whether there is a separate account for this, how he is going to utilise this money or whether he is considering passing on this money to the Maharashtra Government for the purpose for which he has collected that amount.

Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Now, Shri Dineshbhai Trivedi.

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI (Gujrat) : Thank you, Madam Deputy Chairman. I rise today to speak with a lot of anguish and the issue I am going to raise is going to affect ...(*Interruptions*)...

THE DEPUTY CHAIRMAN : One minute, Mr. Trivedi. Mr. Desai wants to associate himself with the previous matter because he also comes from Maharashtra. I will call you after his completion.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Madam, the whole country has expressed its sympathy and extended its help to the victims of the earthquake in Maharashtra. About a year has passed. But these victims are still facing difficulties. Now, monsoon is also setting in. The Chief Minister of Maharashtra has tried his level best to help the victims. I think the World Bank has not yet released the loan. We request the Government—I myself requested the Government—that till the loan from the World Bank was received, the Government of India should advance the loan and it would be given back after the laon of the World Bank was received. So far, the Government of India has not extended that help. I request the Government through you, Madam, and through the Minister for Parliamentary Affairs that efforts should be made to see that the Finance Ministry advances this loan. After the loan of the World Bank is received, this will be given back. If this is done, this problem can be solved. As such, I fully associate myself with what my colleague, Shri Bapu Kaldate, has said. The Maharashtra Government is making all efforts. But if the Finance Ministry advances this loan, this problem can be solved. Meanwhile, for the purpose of temporary constructions, the Central Government should send officials of the Ministry of Urban Development to Maharashtra. They should extend some kind of help. The Central Government, the State Government and other voluntary organisations should do this immediately so that before mansoon sets in, we can complete the temporary constructions.

Need to Reform the present Education System

SHRI DINESHBHAI TRIVEDI : Madam, the issue I am raising today is going to decide the future of this country where wore than 900 million people are living and I am sure that the whole House will associate itself with me.

Madam, Rabindra Nath Tagore, the greatest poet the world has ever seen, had mentioned that our society should be such where the mind is without fear and head is held high. Unfortunately, what we are seeing is just the reverse of this.

I am talking about the atrocities on being inflicted the young mind by our terrible education system. The issue I am raising is not new. The hon. Member, Shri R. K. Narayan, had raised this issue in this very House a few years ago which was reported widely in the country and which had received much attention. Madam, where are we going ? There are